



हवा में प्रदूषण कम करने को उठाए सख्त कदम

निश्चित रूप से इन 16 वर्षों में दुनिया ने काफी बदलाव देखे, लेकिन जहां तक डब्ल्यूएचओ के मानकों को लागू किए जाने का सवाल है, तो उस मोर्चे पर हालात संतोषजनक नहीं रहे। चाहे जैसे भी हो, पर्यावरण को बेहतर बनाने वाले कदम हमें उठाने ही होंगे।

मनोज सिंह।।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने अपनी एयर क्वालिटी गाइडलाइंस में बदलाव लाते हुए हवा की शुद्धता के मानकों को और सख्त बना दिया है। डब्ल्यूएचओ के पुराने मानक 2005 में तय हुए थे। निश्चित रूप से इन 16 वर्षों में दुनिया ने काफी बदलाव देखे, लेकिन जहां तक डब्ल्यूएचओ के मानकों को लागू किए जाने का सवाल है, तो उस मोर्चे पर हालात संतोषजनक नहीं रहे। खुद डब्ल्यूएचओ के आंकड़ों के मुताबिक, 2019 में दुनिया की 90 फीसदी आबादी ऐसी हवा में सांस ले रही थी, जो इसके 2005 के मानकों के मुताबिक हानिकारक थी।

ऐसे में यह सवाल पूछा जा सकता है कि

जब पिछले मानक ही ढंग से लागू नहीं हो पाए हैं तो उन्हें अच्छी तरह लागू करने के बजाय मौजूदा मानकों को और कड़ा बनाने का भला क्या मतलब? क्या इससे यह खतरा नहीं है कि कुछ देश इतना पीछे छूट जाएं कि उनमें इन मानकों को लागू करने का संकल्प ही कमजोर पड़ने लगे? ऐसी आशंका को पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता, लेकिन यह समझना होगा कि पर्यावरण की लगातार बिगड़ती दशा एक ऐसी चुनौती बन गई है, जिससे पूरी ताकत से निपटने के सवाल पर किसी भी तरह के किंतु-परंतु के लिए कोई गुंजाइश नहीं रह गई है। चाहे जैसे भी हो, पर्यावरण को बेहतर बनाने वाले कदम हमें उठाने ही होंगे।



डब्ल्यूएचओ द्वारा एयर क्वालिटी गाइडलाइंस में किए गए ताजा बदलाव भी कानूनी तौर पर बाध्यकारी नहीं हैं, लेकिन इनसे सभी देशों को यह संदेश जरूर जाएगा कि हवा में प्रदूषण कम करने के लिए सख्त कदम उठाना उनके लिए कितना जरूरी हो गया है। आज भी दुनिया में हर साल करीब 70 लाख मौतें खराब हवा में सांस लेने की वजह से हो रही हैं। मगर सवाल सिर्फ इन मौतों का या इस वजह से होने वाली बीमारियों का नहीं है। डब्ल्यूएचओ ने हवा में जिन पीएम 2.5 और पीएम 10 जैसे खतरनाक अवयवों को कम करने का आग्रह नए मानकों के जरिए किया है, उनका मुख्य स्रोत कोयला, पेट्रोल जैसे खनिज ईंधन

का उपयोग है। इन ईंधनों के उपयोग में कमी से से जहां हवा का प्रदूषण कम होगा, वहीं जलवायु परिवर्तन के मोर्चे पर भी राहत मिलेगी।

यानी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से ग्लोबल वॉर्मिंग के चलते विनाशकारी गतिविधियों का जो चक्र घूमना शुरू हो चुका है, उसकी गति भी कुछ नियंत्रित हो सकती है। मगर यह सब निर्भर करता है इस बात पर कि डब्ल्यूएचओ की सिफारिशों को विभिन्न देश कितनी गंभीरता से लेते हैं। भारत भी उन देशों की सूची में है, जो इन सिफारिशों को लागू करने में बहुत पीछे है। ऐसे में इन मानकों को रातोंरात लागू करने की खुशफहमी पालने के बजाय हमें अपने मानकों को जल्द से जल्द लागू करने और उन्हें बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

राहत

अशोक बोहरा।

एक शाम जब राजकुमार सो रहा था, जब बीरबल ने राजकुमार के बजाय सैर के लिए पुतले को ले जाने को

धर्म-दर्शन



सेवक से कहा। सेवक ने वैस ही

किया, जैसा बीरबल ने कहा था। थोड़ी देर बाद वह सेवक अकबर के पास दौड़ते हुए आया और बोला, "जहांपनाह! जल्दी चलिए, राजकुमार तालाब में गिर गए हैं। वह तैरना नहीं जानते हैं।"

अकबर ने यह सुना तो वह अपने सिंहासन से जोर से उछले और तालाब की ओर भागे। जब वह तालाब पर पहुंचे, तो राजकुमार को बचाने के लिए उसमें कूद गये। अकबर को बहुत राहत मिली, जब उन्हें तालाब में राजकुमार के बजाय राजकुमार की तरह दिखने वाला मोम का एक पुतला मिला। बीरबल बादशाह का पानी से बाहर आने के लिए इंतजार कर रहे थे।

संपादकीय

अंधा युग की हकीकत

भारत के विभिन्न बीजेपी-प्रशासित राज्य धर्म-परिवर्तन के विरुद्ध कड़े कानून बना रहे हैं और कई ईसाई और मुसलमान संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। उन्हें शायद पोप से शिकायत होगी कि उन्होंने यह मुद्दा मोदी के सामने क्यों नहीं उठाया। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ ईसाई संगठनों ने तो बाकायदा बीजेपी-विरोधी अभियान भी चला रखा है। लेकिन केरल के प्रसिद्ध ईसाई बिशप कार्डिनल जॉर्ज एलेनचेरी ने मोदी की वैटिकन-यात्रा का स्वागत किया है और माना है कि इस यात्रा से भारत, वैटिकन और कैथलिक चर्च में घनिष्टता बढ़ेगी। वैसे भी भारत के औसत ईसाई को मोदी-पोप भेंट अच्छी ही लग रही है, लेकिन साथ ही साथ यह भी माना जा रहा है कि इस भेंट के द्वारा मोदी ने एक तीर से दो शिकार कर लिए हैं। एक तो अपनी हिंदुत्ववादी कट्टर छवि को नरम कर लिया है, दूसरा सोनिया गांधी, जो कि खुद इतालवी कैथलिक हैं, उनके किले में संध लगा दी है। यह ठीक है कि इस पोप-मोदी मिलन के समय धर्म-परिवर्तन का मुद्दा नहीं उठा, लेकिन इस्लाम और ईसाइयत के लिए इस मुद्दे का महत्व बहुत ज्यादा है। अपने अनुयायियों का संख्या-बल बढ़ाने के लिए इन धर्मध्वजियों ने ऐसे-ऐसे हथकंडे अपनाए हैं, जिन्हें मुनासिब नहीं माना जा सकता। इस बार जब पवित्र पोप भारत आए तो उनसे कहा जाए कि उनके पादरी ईसा के उत्तम विचारों को जरूर फैलाएं, लेकिन सेवा के बदले भारतीयों का धर्म न छीनें।

जो लोग मोदी सरकार और बीजेपी पर सांप्रदायिकता और संकीर्णता का आरोप लगाते हैं, वे काफी असमंजस में हैं कि मोदी को क्या सूझी कि पोप से मिल लिए।

क्या सूझी कि पोप से मिल लिए

वेदप्रताप वैदिक।।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यों तो सभी विदेशी नेताओं से गल-मिलव्वल करने के लिए जाने जाते हैं। अन्य देशों के बादशाह, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री यदि हमारे प्रधानमंत्री की गर्मजोशी का जवाब उसी गर्मजोशी से देते हैं तो यह स्वाभाविक है। लेकिन पोप फ्रांसिस, जो कि दुनिया के सबसे बहुसंख्यक धर्म के शीर्षपुरुष हैं, उनका एक राजनेता के साथ इतना स्नेहिल मिलन अपने आप में एक कथानक है। जो लोग मोदी सरकार और बीजेपी पर सांप्रदायिकता और संकीर्णता का आरोप लगाते हैं, वे काफी असमंजस में हैं कि मोदी को क्या सूझी कि पोप से मिल लिए। वे शायद भूल रहे हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी भी 2000 में अपनी रोम-यात्रा के दौरान पोप से मिले थे और जब 2005 में पोप जॉन पॉल-2 का निधन हुआ तो उनके अंतिम संस्कार में भारत के उप-राष्ट्रपति भैरोंसिंह शेखावत वैटिकन गए थे। ये दोनों बीजेपी के शीर्ष नेता थे।

संपूर्ण ईसाई जगत में यह माना जाता है कि पोप से ज्यादा पवित्र कोई नहीं। ईसाई ही नहीं, अन्य धर्मावलंबी भी जब रोम जाते हैं तो पोप के दर्शन करने की अपनी इच्छा पूरी करते हैं। 1969 में इंदौर के कैथलिक सहपाठियों ने जब मुझे बुलाया था तो मैं भी मॉस्को से सीधा रोम गया और वैटिकन में मैंने भी पोप को देखा।



मोदी और वाजपेयी ही नहीं, देश के चार अन्य प्रधानमंत्रियों ने भी वैटिकन जाकर तत्कालीन पोपों से भेंट की। 1955 में जब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू वैटिकन जाकर पोप पायस-12 से मिले, तब पुर्तगाल की सरकार ने बड़ी आपत्ति की और आरोप लगाया कि नेहरू सरकार गोवा के ईसाइयों पर भयंकर अत्याचार कर रही है, लेकिन प्रधानमंत्री नेहरू ने यूरोपीय पत्रकारों से कहा कि गोवा के मामले का मजहब से कोई लेना-देना नहीं है। वह शुद्ध राजनीतिक मामला है। उन्होंने यह भी बताया कि पोप से हुई बातचीत में गोवा का जिक्र आया, लेकिन पोप उनके जवाब से संतुष्ट हुए। पोप से प्रधानमंत्री के तौर पर इंदिरा गांधी 1981 में मिलीं और प्रधानमंत्री इंदर गुजराल 1997 में मिले।

हमारे पांचों प्रधानमंत्रियों की जो भेंट पोप से हुई, उसका कारण जितना उनका धर्माध्यक्ष होना है, उससे ज्यादा उनका राष्ट्रध्यक्ष होना है। वे वैटिकन नामक राज्य के राष्ट्राध्यक्ष हैं। इस राज्य को 1948 में भारत बाकायदा राजनयिक मान्यता दे चुका है। इसी हैसियत में सभी पोप विभिन्न देशों की राजकीय-यात्रा भी करते हैं। भारत में पहली बार पोप पॉल-4 1964 में आए थे। पोप जॉन पॉल-2 1986 और 1999 में भारत आए थे। पोप जॉन पॉल की दूसरी यात्रा के समय भारत में तगड़ा विवाद उठ खड़ा हुआ था। उस समय ईसाई पादरियों द्वारा धर्म-परिवर्तन के लिए जो हथकंडे अपनाए जा रहे थे, उनकी काफी चर्चा थी। विश्व हिंदू परिषद के नेताओं ने उस धर्मांतरण को घोर अनैतिक तो बताया ही था, साथ-साथ पोप के लिए कई आपत्तिजनक शब्दों का भी इस्तेमाल कर दिया था, जिसका बीजेपी ने भी विरोध किया था।

आजकल भारत में बीजेपी, संघ और हिंदुत्ववादी शक्तियों की प्रबलता है, शायद इसी संकोच के कारण वर्तमान पोप फ्रांसिस अभी तक भारत नहीं आए। हालांकि भारत में कैथलिकों की आबादी लगभग 2 करोड़ है, जो कि फिलीपींस के बाद एशिया में सबसे ज्यादा है। बहरहाल, इस बार उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है।

सूटिकू बवताल-5345				सूटिकू बवताल-5344 का हल			
5		3		4	2	5	8
2		9	5	7	3	1	9
9			6	6	9	8	7
				3	5		
	6				7		
4	8						
		7					3
		2	4			9	
		8			2		

अपना ब्लॉग

पवित्रता और क्रांतिकारी दृष्टिकोण का परिचय

मोहन। गोवा में होने वाले चुनावों में इस यात्रा का लाभ लेकर बीजेपी ईसाई वोटों को तो पटाएगी ही, वह केरल-जैसे कैथलिक-बहुल प्रांत में भी पैठ बनाएगी। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ई. के. नयनार भी 1997 में पोप से मिले थे और उनके साथ वर्तमान कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री पिनरारी विजयन भी थे। इसीलिए यूरोप के विख्यात बुद्धिजीवियों वाल्टेयर, विक्टर ह्यूगो, कर्नल इंगरसोल और बुकनर आदि ने ईसाइयत के परखचे उड़ा दिए थे। यूरोप के इतिहास में उस एक हजार साल की अवधि को अंधा-युग कहा जाता है, जिसमें पोप का वर्चस्व रहता था। उस काल में पोपों को कई ईसा-विरोधी कुत्सित कर्म करते हुए पाया गया था। लेकिन पिछले कुछ पोपों ने अपने विचार और व्यवहार में उच्चता तथा पवित्रता और क्रांतिकारी दृष्टिकोण का परिचय दिया है। इस बार मोदी और पोप की जो भेंट सिर्फ 20 मिनट की होनी थी, वह एक घंटे तक चली। उसमें न तो धर्म-परिवर्तन का विवादास्पद मुद्दा उठा और न ही धार्मिक-प्रताड़ना का।

